

दीघा-पटना रेल लाइन की जमीन सरकार को देने का आश्वासन

● पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने रेल मंत्री से की मुलाकात

संवाददाता ▷ पटना

पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर



आरओबी निर्माण सहित पथ निर्माण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया. रेल मंत्री से बातचीत के

दौरान दीघा घाट से पटना जंक्शन, पटना साहिब से पटना घाट तक पुरानी रेलवे लाइन की भूमि को फोर लेन सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार को देने के बिंदु पर चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से भारत सरकार इस पर सहमत है.

रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार विचार-विमर्श करके नया प्रस्ताव बनाये ताकि जल्द-से-जल्द यह भूमि उचित शर्तों पर राज्य सरकार को दी जा सके. केंद्रीय सरकार व राज्य सरकार दोनों इसमें मिल कर

आगे की कार्रवाई कर रही हैं, ताकि दीघा घाट से पटना जंक्शन व पटना जंक्शन से पटना साहिब तक फोर लेन का रास्ता प्रशस्त हो सके.

आरओबी का निर्माण इरकॉन से कराने का निर्णय :

पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य में 47 जगहों पर नयी आरओबी बनाने की योजना पर चर्चा हुई. आरओबी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 50 फीसदी राशि अपने संसाधनों से खर्च करने की सहमति प्रदान कर दी है. मंत्री ने आरओबी बनाने व निर्माण का काम एक ही एजेंसी से कराने का अनुरोध किया. आरओबी निर्माण में एप्रोच रोड भी उसमें शामिल है. राज्य सरकार ने इरकॉन से कार्य कराने हेतु निर्णय लिया है. रेल मंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी है. रेल मंत्रालय के पदाधिकारियों को 38 आरओबी की डीपीआर बनाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. राज्य में 47 में से 8 स्थानों पर आरओबी का कार्य प्रारंभ हो गया है. एक स्थान पर टेंडर व 38 स्थानों पर निर्माण के लिए डीपीआर बनानी है. मंत्री ने कहा कि रेल मंत्री के इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य में आरओबी के निर्माण में तेजी आयेगी.